अनुलग्नक

अप्रैल, 2023 माह की आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की प्रमुख गतिविधियों का मासिक सारांश

I. स्वच्छ भारत मिशन

i. सभी 4,715 शहरों/कस्बों को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित किया गया है, जिनमें से 4,355 शहरों को तृतीय पक्ष सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, 3,547 शहरों को ओडीएफ + के रूप में प्रमाणित किया गया है, 1191 शहरों को ओडीएफ++ के रूप में प्रमाणित किया गया है। और 14 शहरों (इंदौर, सूरत, नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), तिरुपति, चंडीगढ़, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, हैदराबाद, ग्रेटर विशाखापट्टनम, करड, पंचगनी, भोपाल, बारामती और मैसूर) को वॉटर+ के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ii. एसबीएम शौचालय के नाम से गूगल मैप्स पर 3,326 से अधिक शहरों के 67,407 शौचालय लाइव हैं।

iii. स्वच्छता ऐप नागरिकों को संबंधित नगर निगम द्वारा अपनी शिकायतों का समाधान करने में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा।" स्वच्छता ऐप के कुल 2.08 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, जिन्होंने 2.55 करोड़ शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें से 2.39 करोड़ शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जो कुल शिकायतों का 94% से अधिक है।

iv. जीएफसी2022 का परिणाम स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह 2022 के रूप में 01 अक्टूबर 2022 को घोषित किया गया था। कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के लिए स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत 7-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 1 है, 5-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 11 है, 3-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या199 है और 1-स्टार प्रमाणन वाले शहरों की संख्या 234 है।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ साझेदारी में यूएनआईडीओ की परियोजना संचालन सलाहकार समिति की सातवीं बैठक 13 अप्रैल, 2023 को आयोजित की गई थी। इनकी चर्चा कार्बो न्यूट्रल और नेचर पॉजिटिव शहरों को डिजाइन करने से संबंधित थी।

II. स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम)

i. 180,177 करोड़ रुपये की 7,857 परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें से 1,06,722 करोड़ रुपये की 5,713 परियोजनाएं पहले ही पूर्ण की जा चुकी हैं। माह के दौरान 337 करोड़ रुपए की 86 अतिरिक्त परियोजनाएं भी पूर्ण कर ली गई हैं।

ii. जापान-भारत संयुक्त कार्य समूह के तहत 19.04.2023 को एक स्मार्ट सिटी उप-समूह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों देशों के उद्योग भागीदारों ने भाग लिया। भारत से, टेक महिंद्रा, कांटेला, विप्रो, एल एंड टी, और फ्लुएंटग्रिड ने बैठक में भाग लिया। जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ कैनन कॉर्पोरेशन, एनईसी कॉर्पोरेशन, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदि कंपनियां थीं।

iii. डेटा और प्रौद्योगिकी पर तीसरा स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन 27 अप्रैल 2023 को चंडीगढ़ में विभिन्न विषयों जैसे शहरों द्वारा केस ऑपरेशन प्रेजेंटेशन, आईसीसीसी मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क (आईएमएएफ) शहरों द्वारा प्रेजेंटेशन और शहरों द्वारा बिजनेस प्लान ओवरव्यू और प्रेजेंटेशन आदि पर 100 स्मार्ट शहरों के अनुभव साझा करने के लिए आयोजित किया गया था।

iv. 28 अप्रैल 2023 को सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का साइक्लिंग टूर और योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भारत भर के 100 स्मार्ट शहरों के प्रतिनिधियों ने डेटा और टेक्नोलॉजी पर स्मार्ट सिटीज सीईओ सम्मेलन में भाग लिया।

III. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

i. सभी राज्यों के लिए 77,640 करोड़ रुपए की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को अंतिम रूप दिया गया है। आज की स्थिति के अनुसार, 83,368 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई है। अमृत के कार्यान्वयन में प्रगति: 77,640 करोड़ रुपये की स्वीकृत कार्य योजनाओं से अधिक 83,368 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी गई है। कुछ राज्यों ने अपने अनुमोदित एसएएपी से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें सीमा से अधिक की राशि राज्यों/यूएलबी द्वारा वहन की जाएगी। 37,522 करोड़ रुपये की 4,910 परियोजनाओं के लिए कार्य पूरा कर लिया गया है और 45,231 करोड़ रुपये की 987 परियोजनाओं के लिए कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर/चल रही अमृत परियोजनाओं में लगभग 70,901 करोड़ रुपये का वास्तविक कार्य किया गया है, जिसका अर्थ है कि लगभग 91% वास्तविक कार्य पूरा हो गया है।

ii. अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना कार्यान्वयन (पूर्ववर्ती जेएनएनयूआरएम की पात्र परियोजनाओं सहित), प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (एएंडओई), सुधार प्रोत्साहन और 'अमृत शहरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान बनाने' और 'स्थानीय क्षेत्र योजना (एलएपी) और 25 चयनित शहरों में टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) पर उप-योजनाओं के तहत 38,134 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

IV. दीनदयाल अंत्योदय योजना/राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई/एनयूएलएम)

i. चालू वित्त वर्ष के अप्रैल महीने के दौरान 1,695 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) गठित किए गए हैं; 1,880 एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड दिया गया था; 562 लाभार्थियों को व्यक्तिगत और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण दिए गए और एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को 1089 ऋण दिए गए।

V. प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

i. पीएम पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएमएसवीनिधि) के तहत, 64,83,419 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए 48,22,396 स्वीकृतियां और 44,77,888 संवितरण किए गए हैं।
ii. अप्रैल, 2023 के महीने के दौरान मिशन के तहत कुल 3.18 लाख रूपए जारी किए गए हैं।

VI. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)/सभी के लिए आवास (एचएफए)

i. स्थापना के बाद से, मिशन ने 1.20 करोड़ आवासों को मंजूरी दी है, जिनमें से 110.20 लाख आवास निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 73.61 लाख आवासों को पूरा/ सुपुर्द किया जा चुका है।

VII. आवास

i. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने नागालैंड को छोड़कर रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित किया है, नागालैंड नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।
ii. 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (नियमित - 26, अंतरिम - 06) की स्थापना की है। लद्दाख, मेघालय और सिक्किम ने प्राधिकरण स्थापित करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है।
iii. 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (नियमित-24, अंतरिम-04) स्थापित किया है (अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं)।
iv. 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियामक प्राधिकरणों ने रेरा के प्रावधानों के तहत अपनी वेबसाइट शुरू की है। *(अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर चालू करने की प्रक्रिया में हैं) /*
v. देश भर में रेरा के तहत 1,02,985 भूसंपदा परियोजनाओं और 72,662 एजेंटों ने अपना पंजीकरण करवाया है।
vi. देश भर में भूसंपदा नियामक प्राधिकरणों द्वारा 1,07,146 शिकायतों का निपटान किया गया है। मार्च 2023 के दौरान 1387 परियोजनाओं और 293 एजेंटों को पंजीकृत किया गया है।